

No.IV-18011/1/2013-Prov.I 461
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
P.M. Division

26, Mansingh Road, Jaisalmer House,
New Delhi, dated 27th February, 2014.

To

Shri Sonu Singh,
Gram- Sahijana Road,
Near Sahijana Mill,
Post- Gadwa,
Gadwa (Jharkhand)-822114

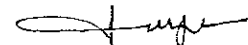
Subject: Information sought by shri Sonu Singh under the Right to Information Act, 2005- Regarding.

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 29-11-2013 received by this Division on 30-01-2014 through CS Division, MHA on the subject mentioned above and to say that the undersigned CPIO is not concerned with the subject matter.

2. Smt. Veena Kumari Meena, Joint Secretary (PM) MHA, Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi is the Appellate Authority in respect of P.M. Division.

Yours faithfully,



(S. K. Jain)
Director (Prov) & CPIO
Tele. No. 23386191

Copy to:

1. Sh. K. Muralidharan, Dir(CSF-II), MHA w.r.t. their letter No. IV-/16015/17/2011-/CSR-II dated 28-01-2014.

O/C

4/02/14
98/9/2014

5804/RTI/2011

9/12

2603/RTI/CR
2011

213

सूचना का अधिकार आवेदन

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत)

प्रेषक,

दिनांक 29.11.11

सानू सिंह,

ग्राम - सहीजना रोड, नजदीक सहिजना मील

पो 0 + जिला - गढ़वा

झारखण्ड - 822114

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी,

केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार,

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत उपबन्धित प्रावधानों के तहत मांगे गए दिवसों से संबंधित सही एवं अपेक्षित सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में।

नहाशय

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित कारण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन उपबन्धित संवैधानिक प्रावधानों के आलाोक में मांगे गए दिवसों से संबंधित वांछित सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ अधोहस्ताक्षरी को अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की संवैधानिक समयवाधि के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

मांगी जा रही सूचना बिबू विम्बांकित हैं :-

- यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून 2005 के समको रूप से अनुपालन किए जाने हेतु माननीय भारत सरकार को अंतरदायी स्तर से जारी निर्देशों व आदेशों की वांछित प्रति उपलब्ध करावी जाए।
- यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून लागू होने के पश्चात अबतक कितने ऐसे लोग हैं जो कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने के कारण हताहत हुए हैं। वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाए।
- यह कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने वाले लोगों को सुरक्षा व संरक्षण देने के निमित्त माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेशों व निर्देशों की वांछित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

DSCCS/
DEPT

NIL

NIL

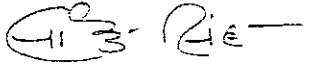
NIL

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रूप में निर्धारित ₹10/- रु0 की राशि का भुगतान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन उपबन्धित प्रावधानों के अनुरूप मूल रूप में सूचना का अधिकार आवेदन के साथ समर्पित किया जा रहा है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अंकित सूचना बिन्दुओं से संबंधित वांछित एवं सही सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित 30 दिनों की समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। सूचना उपलब्ध कराने के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि की गणना सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन नियम) 2005 की धारा 4 के अनुरूप गणित की जाए। साथ ही साथ पन्नों की संख्या को सूचना बिन्दुवार रूप से उल्लेखित किया जाए। निवेदन है कि विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का विलापन नहीं किया जाए।

सहयोग के लिए धन्यवाद।

विश्वासभाजक



(सोनू सिंह)

(आवेदक)

स्थान राइवा / दिनांक 29.11.11

अनुलग्नक संलग्न :-

1. सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रूप में नूतन रूपये ₹ 10. /- की राशि प्रावधानों के अनुकूल पोस्टल ऑर्डर संख्या 66E118212 द्वारा मूल रूप में समर्पित।